साप्ताहिक

जागत गांव हमार

पंचायत की विकास गाथा, सरकार तक

RNI-MPHIN/2015/72544

चौपाल से भोपाल तक

भोपाल, सोमवार, 22-28 जुलाई 2024 वर्ष-10, अंक-15

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, मुरैना, रीवा, शिवपुरी से एक साथ प्रकाशित

पृष्ठः-8,मूल्यः- 2 रुपए

» सीएम बोले-प्रदेश में विकसित किए जाएंगे आयुर्वेदिक केंद्र

» स्वावलंबन, भारतीय गांवों की है मुख्य शक्ति और विशेषता

-मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की घोषणा से पशु पालक हुए खुश

दस से अधिक गाय पालने वाले किसानों को अनुदान देगी सरकार

कांजी हाउस को गौशाला के रूप में विकसित किया जाएगा

भोपाल। जागत गांव हमार

मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव ने दस से अधिक गाय पालने पर अनुदान देने की घोषणा की है। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में सीएम ने कहा-ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार खेती है। किसानों की जब आय बढ़ती है तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। इसके लिए पशुपालन को महत्व दिया जा रहा है। जो किसान 10 से अधिक गाय पालेंगे, उन्हें अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। आत्मनिर्भर पंचायत-समृद्ध मध्य प्रदेश पर आयोजित संगोष्ठी में सीएम ने कहा कि वृद्ध, अस्वस्थ, अपाहिज व असहाय गायों को पालने के लिए कांजी हाउसों को गौशाला के रूप में विकसित किया जाएगा। उपज के समान ही दूध पर बोनस उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी आरंभ की जा रही है। गौपालन को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष नीति बनाई जा रही है।

आयुर्वेदिक केंद्रों का विकास, बहनों के समूह की आय बढ़ाने के प्रयास

आत्मनिर्भर पंचायत-समृद्ध मध्य प्रदेश पर आयोजित संगोष्ठी में सीएम ने कहा-प्रदेश में आयुर्वेदिक औषधियों की भरपूर संपदा है। प्रदेश में आयुर्वेदिक केंद्र भी विकसित किए जाएंगे। लघु, कुटीर उद्योग तथा बहनों के स्व-सहायता समूहों के उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने व आय में वृद्धि के लिए हरसंभव व्यवस्था की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मंशा के अनुरूप किसान, महिला, युवा और गरीब को जोड़ते हुए, उन्हें सशक्त बनाते हुए मध्य प्रदेश आगे बढ़ेगा।

हर खेत में हो रही सिंचाई

मुख्यमंत्री ने कहा-हर घर में नल से जल उपलब्ध कराने के लिए जल जीवन मिशन चलाया जा रहा है। हर खेत में सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था के उद्देश्य से स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार प्रयास किए जा रहे हैं। केन-बेतवा लिंक परियोजना के लिए मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को 45-45 हजार करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए हैं। कालीसिंध-पार्वती और चंबल लिंक परियोजना की गतिविधियां आरंभ हो रही हैं।

गौ-पालन को बनाएंगे लाभ का धंधा

इधर, मुख्यमंत्री ने केरवा डेम बुल मदर फार्म का निरीक्षण किया। उन्होंने गायों को हरी घास खिलाई और दुलार भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार गौ-वंश को गौ-शालाओं में रखने का पूरा प्रयास कर रही है। वर्षा काल में कोई भी गौ-वंश सड़कों पर न रहे इसके लिए उन्हें गौ-शालाओं में रखा जा रहा है। गौ-शालाओं की क्षमता भी बढ़ाने के प्रयास जारी हैं। किसानों और गौ-पालकों की आय बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। गौ-पालन को लाभ का धंधा बनाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। देशी नस्ल को बढ़ावा दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि गौ-वंश को प्रोत्साहन देने के लिए योजना बनाई जाए। उन्होंने दूध पर सब्सिडी देने एवं केंद्र और राज्य शासन की विभिन्न स्कीमों पर चर्चा की। गौ-पालकों को लाभान्वित करने के सभी आवश्यक प्रयास किए जाएं।

पंचायतों के सम्मुख चुनौतियां

पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि आत्मनिर्भर पंचायत-समृद्ध मध्यप्रदेश पर संगोष्ठी पंचायतराज व्यवस्था को अधिक प्रभावी और सशक्त बनाने में मील का पत्थर सिद्ध होगी। कृषि को लाभकारी बनाने, हरित मध्यप्रदेश, शहरीकरण से पंचायतों पर प्रभाव, केन्द्र पोषित योजनाओं का क्रियान्वयन, पेसा अधिनियम का क्रियान्वयन तथा वन क्षेत्र से लगी पंचायतों के सम्मुख चुनौतियों पर चर्चा के साथ ही ई-पंचायत व्यवस्था और पंचायतों की कार्य प्रणाली में वित्तीय अनुशासन तथा पारदर्शिता आदि विषयों पर चर्चा होगी।

-पंचायत मंत्री ने कहा-ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने 1000 होमस्टे बनेंगे

पूरी लगन से कर्तव्यों का पालन करें, अधिकार स्वाभाविक रूप से मिलेंगे

हर पंचायत में सामुदायिक भवन और अपना भवन होगा

भोपाल। जागत गांव हमार

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रह्लाद सिंह पटेल ने पंचायत प्रतिनिधियों का आह्वान किया है कि वे पूरी लगन से अपने कर्तव्यों का पालन करें। अधिकार तो स्वाभाविक रूप से मिल जाएंगे। राज्य सरकार पूरे प्रयास कर रही है कि हर पंचायत में सामुदायिक भवन हो और हर पंचायत का अपना भवन हो। हर पंचायत अपने क्षेत्र के विकास कार्यों की प्लानिंग क्षमता और समझदारी से कर सकती है। पंचायत राज एक साथ मिलकर जनकल्याण के लिए कार्य करने की भावना है। जनपद पंचायत उपाध्यक्षों की सहमति के लिए अनिवार्य रूप से उन्हें नस्ती भेजने संबंधी आदेश जल्दी ही जारी कर दिए जाएंगे। दरअसल, मंत्री यहां आत्मनिर्भर पंचायत- समृद्ध मध्यप्रदेश विषय पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग और जीआईजेड द्वारा आयोजित कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने जनपद पंचायत, उपाध्यक्षों से आग्रह किया वे ऐसे कार्यों और गतिविधियों की सूची बना लें जिनमें वे समझते हैं कि उनका मत और सहमति आवश्यक हो। पंचायतों को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनके आंतरिक प्रशासनिक तंत्र को मजबूत बनाने की कार्रवाई चल रही है। निचले स्तर पर प्रशासनिक तंत्र की मजबूती आवश्यक है।

117 गांवों में होम स्टे बनेंगे

पंचायत मंत्री ने कहा कि विभिन्न योजनाओं में उपलब्ध बजट राशि और वित्तीय संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना चाहिए। अंतिम उद्देश्य लोगों को खुश करना और उनकी भलाई करना है। वहीं पर्यटन मंत्री धर्मेन्द्र सिंह लोधी ने बताया पर्यटकों को प्रदेश की समृद्ध ग्रामीण संस्कृति से परिचित कराने के लिए ग्रामीण पर्यटन योजना में पर्यटन के माध्यम से गांवों की आय बढ़ाने के लिए 117 गांवों में होम स्टे निर्माण किया जाएगा।

1000 होमस्टे बनाने का लक्ष्य

सरकार द्वारा 1000 होमस्टे बनाने का लक्ष्य है। जनजातीय क्षेत्रों में 60 और गैर, जनजातीय क्षेत्रों में 40 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाएगा। पर्यटकों को ग्राम भ्रमण, ग्रामीण खेल, आरामदायक स्टे, स्थानीय भोजन, लोक कला और हस्तशिल्प से परिचित कराया जाएगा। स्थानीय युवकों को आनलाइन पर्यटन गाइड का प्रशिक्षण दिया जाएगा। कार्यशाला में गौवंशों का संरक्षण और संवर्धन, डिजी लाकर, जल गंगा संवर्धन अभियान, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण, स्वच्छ भारत मिशन, ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण पर जानकारी दी गई।

इंदौर में एक पेड़ मां के नाम पौधरोपण को मिली सराहना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में किया जिक्र

भोपाल। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आकाशवाणी के मासिक कार्यक्रम मन की बात के अंतर्गत मध्यप्रदेश में एक पेड़ मां के नाम अभियान में हुए विशेष कार्य का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इंदौर में एक ही समय लाखों पौधों का रोपण किया गया है, जो अपने आप में अनूठा है। उन्होंने कहा कि पिछले मन की बात कार्यक्रम के अंतर्गत एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम की चर्चा की थी। देश के अलग-अलग हिस्सों में एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत अच्छे कार्य हुए हैं। स्वच्छता के लिए अपनी पहचान बनाने वाले इन्दौर शहर में एक शानदार कार्यक्रम हुआ जिसमें एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के दौरान एक ही दिन में एक वक्त में लाखों पौधे लगाए गए। प्रधानमंत्री ने नागरिकों से आह्वान किया कि अपनी मां के नाम पेड़ लगाने के इस अभियान से प्रत्येक नागरिक जुड़ें। साथ ही पौधा लगाने की सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पर अवश्य शेयर करें, जिससे अन्य लोग भी इससे प्रेरित होकर अभियान से जुड़ें। इस अभियान से जुड़कर नागरिकों को अपनी मां और धरती मां दोनों के लिए कुछ विशेष कर पाने का अहसास होगा। प्रदेश में अधिकारी-कर्मचारी, वरिष्ठ नागरिक और युवा भी एक पेड़ मां के नाम अभियान में बढ़-चढ़कर भागीदारी कर रहे हैं।

अभियान के लिए विशेष प्रोत्साहन

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के विशेष प्रयास और प्रोत्साहन से मध्यप्रदेश में 'एक पेड़ मां के नाम अभियान में निरंतर पौधे लगाए जा रहे हैं, जिसमें मंत्रीगण, सांसद, विधायक, सभी जनप्रतिनिधि सहित आम नागरिक भी पौध-रोपण कार्यक्रमों में शामिल हुए हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी जिलों में एक पेड़ मां के नाम अभियान को सफल बनाने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने अधिकारी-कर्मचारी, सामाजिक संस्थाओं और नागरिकों को भी इस अभियान में व्यापक भागीदारी का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री के आह्वान पर सभी जिलों में पौध-रोपण जारी है। पौधरोपण के साथ लोग संरक्षण का संकल्प भी ले रहें हैं।

-अबकी बार! आंध्र-बिहार... जिनके समर्थन से सरकार, उनके लिए खुले भंडार

-निर्मला ने 1 घंटे 23 मिनट के भाषण में नौ सूत्रीय योजनाओं का एलान किया

-बाढ़ से निपटने के लिए 25 हजार बस्तियों में बनेगी मौसम के अनुकूल सड़क

-टूरिज्म पर विशेष जोर, ओडिशा के पर्यटन को बढ़ावा देगी सरकार

अन्न भंडार क्षमता में होगा इजाफा

खेत-खलिहान को संजीवनी

भोपाल/नई दिल्ली। प्रधान संपादक

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सातवीं बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड बनाया। भाषण में उनका फोकस शिक्षा, रोजगार, किसान, महिला और युवाओं पर रहा। कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए 1.52 लाख करोड़ का बजट दिया गया है। 2023-24 की तुलना में यह 7,637 करोड़ ज्यादा है। खेती-बागवानी की 32 फसलों की जलवायु अनुकूल और अधिक पैदावार वाली 109 किस्में लाने की तैयारी है। विकसित भारत का लक्ष्य पाने के लिए जिन नौ सेतुओं का संतुलन सरकार ने बनाया है, उनमें खेत-खलिहान और किसान को प्राथमिकता पर रखा गया है। फसलों का उत्पादन बढ़ाकर जहां किसानों को मजबूत किया जाएगा। वहीं, बेहतर बाजार देने की मंशा से भंडारण क्षमता में वृद्धि की जाएगी। खराब मौसम और जलवायु परिवर्तन से खेती और बागवानी की फसलों को बचाया जाएगा। इसके लिए 32 फसलों की 109 किस्में लाई जाएंगी। यही नहीं, 400 जिलों में किसानों का ब्योरा भी डिजिटल किया जाएगा।

न्यू टैक्स रिजीम चुनने वाले करदाताओं को भी राहत दी है। साथ ही युवाओं और छात्रों के लिए भी योजनाओं की झड़ी लगा दी। इसके अलावा नीतीश कुमार के बिहार और चंद्रबाबू नायडू के आंध्र प्रदेश पर केंद्र सरकार मेहरबान रही। पहली नौकरी वाले जिनकी सैलरी 1 लाख से कम होगी, उन्हें सरकार अधिकतम 15 हजार तीन किश्तों में देगी।

इनकम टैक्स | नई टैक्स रिजीम में बदलाव, सालाना 17,500 रुपए बचेंगे

रोजगार | पहली नौकरी वालों को 15 हजार रुपए की मदद करेगी सरकार

घर | पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ परिवारों को मिलेंगे घर

शिक्षा | देश में हायर एजुकेशन के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा

किसान | कृषि और उससे जुड़े सेक्टरों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए आवंटित

महिलाएं | महिलाओं-बालिकाओं से जुड़ी योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए

हेल्थ | कैंसर की तीन और दवाओं को कस्टम ड्यूटी से मुक्त किया गया

इंफ्रा | 11 लाख करोड़ का बजट, बिहार में दो एक्सप्रेस-वे और एक नया पुल बनेगा

रक्षा | 2024-25 में रक्षा मंत्रालय को 6.21 लाख करोड़ रुपए का बजट मिला

कॉर्पोरेट | विदेशी कंपनियों पर कॉर्पोरेट टैक्स की दर 40 से घटाकर 35 फीसदी की गई

बजट-2024-25 की प्राथमिकताएं

» कृषि क्षेत्र में उत्पादकता और लचीलापन
» रोजगार एवं कौशल
» समावेशी मानव संसाधन विकास एवं सामाजिक न्याय
» विनिर्माण एवं सेवाएं
» शहरी विकास
» ऊर्जा संरक्षण
» अवसंरचना
» नवाचार, अनुसंधान एवं विकास
» नई पीढ़ी के सुधार

ये चीजें सस्ती

» कैंसर से जुड़ी तीन दवाओं पर कस्टम ड्यूटी हटाई गई।
» एक्सरे ट्यूब और फ्लैट पैनल डिटेक्टर पर भी आयात शुल्क हटाया गया।
» मोबाइल फोन और पार्ट्स-पीसीबी और चार्जर पर कस्टम ड्यूटी 15 फीसदी घटी।
» 25 आवश्यक खनिजों पर सीमा शुल्क नहीं।
» सोलर सेल और सोलर पैनल के निर्माण की वस्तु पर टैक्स में छूट।
» सोने और चांदी पर सीमा शुल्क घटाकर छह फीसदी किया गया। ज्वैलरी सस्ती होंगी।
» प्लैटिनम पर सीमा शुल्क घटकर अब 6.4 फीसदी हुआ।
» मछलियों के भोजन पदार्थों पर आयात शुल्क पांच फीसदी करने का निर्णय।

ये महंगा

» पीवीसी फ्लेक्स बैनर का आयात करना महंगा होगा।
» कुछ दूरसंचार उपकरणों का आयात महंगा होगा। आधारभूत कस्टम ड्यूटी 10से बढ़ाकर 15 फीसदी की गई।
» एक साल से ज्यादा तक रखे गए इक्विटी निवेश महंगे होंगे। टैक्स 15 से 20 फीसदी किया गया।
» एक साल से रखे गए शेयर महंगे होंगे। टैक्स 10 फीसदी से बढ़ाकर 12.5 फीसदी किया गया।
» अमोनियम नाइट्रेट पर आयात शुल्क 10 फीसदी बढ़ाया गया।
» खुद से नष्ट न होने वाले प्लास्टिक महंगे होंगे। आयात शुल्क 25 फीसदी बढ़ाया गया।

प्रमुख घोषणाएं

» टैक्स एक्ट की समीक्षा की जाएगी।
» इनकम टैक्स व्यवस्था को आसान बनाया जाएगा।
» टीडीएस समय पर नहीं देना अब अपराध नहीं होगा।
» कैपिटल गेन टैक्स आसान किया जाएगा।
» 6 करोड़ किसानों की जमीन का ब्योरा लैंड रजिस्ट्री पर लाया जाएगा।
» 5 राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे।
» पीएम आवास योजना का विस्तार, 2 लाख करोड़ का प्रावधान
» सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का विस्तार
» एक करोड़ घरों को 300 यूनिट तक हर महीने बिजली फ्री मिलेगी
» मुद्रा योजना में अब मिलेगा 20 लाख तक का लोन
» 5 राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने का एलान

केंद्रीय बजट समावेशी विकास और भविष्य की दृष्टि से तैयार किया गया है, जिसमें सभी क्षेत्रों को प्रगति की राह पर

ले जाने का प्रयास किया गया है। बजट में ग्रामीण और शहरी विकास, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, आधारभूत संरचनाओं, उद्योग, और स्टार्ट-अप सहित सभी क्षेत्रों को संतुलित तरीके से प्राथमिकता दी गई है।
-राजेन्द्र शुक्ल, डिप्टी सीएम

बजट भारत के संपूर्ण विकास और जनता के विश्वास का है। भारत के भविष्य को नई दिशा देने वाला और गरीबों, नारी शक्ति,

युवाओं और किसानों का बजट है। युवाओं के लिए नई आशाएं जगाने वाला बजट है। बजट में रोजगार पर विशेष फोकस किया गया है। बजट में किए गए प्रावधानों से मध्यप्रदेश के विकास पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा।
-जगदीश देवड़ा, वित्त मंत्री

केंद्रीय बजट देश, युवाओं, महिलाओं, किसानों, गरीबों और समाज के हर वर्ग को ताकत देगा। केंद्र ने देश को सशक्त,

समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प जताया है। हर वर्ग के लिए मोदी की गारंटी को पूरा करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। बजट विराट संकल्प की पूर्ति के लिए एक मजबूत नींव का निर्माण करेगा।
-वीडी शर्मा, प्रदेशाध्यक्ष भाजपा

बजट में कई वर्गों के कल्याण और देश के विकास की स्पष्ट झलक दिखती है। युवाओं को स्व-रोजगार उपलब्ध

कराने के उद्देश्य से मुद्रा लोन को 10 लाख से बढ़ा कर 20 लाख कर दिया गया है। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों को राहत देने के उद्देश्य से दवाओं पर लगने वाली ड्यूटी खत्म कर दी गई है।
-गोविंद सिंह राजपूत, मंत्री

केंद्रीय बजट समावेशी और भविष्योन्मुखी विकास का बजट है जिसमें सभी क्षेत्रों को प्रगति का ध्यान रखा गया है। ऊर्जा, ग्रामीण

और शहरी विकास, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, आधारभूत संरचनाओं, उद्योग, और स्टार्ट-अप सहित सभी क्षेत्रों को महत्व दिया गया है। युवाओं को प्रशिक्षण और एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ने का लक्ष्य है।
-प्रद्युम्न सिंह तोमर, मंत्री

बजट उन्नत बुनियादी ढांचे, नवाचार, और अगले स्तर के सुधारों के साथ एक समृद्ध भविष्य का अग्रदूत है, जो समाज

के हर वर्ग के विकास पर केंद्रित है। यह बजट कृषि में उत्पादकता को बढ़ावा देने, रोजगार और कौशल को बढ़ाने और मानव संसाधनों तथा सामाजिक न्याय को और ऊंचा उठाने का वादा करता है।
-राकेश सिंह, मंत्री

-अब उन्नत ग्राम अभियान में 63 हजार गांव शामिल होंगे

-सरकार छोटे कारोबारियों को बिना गारंटी के लोन देगी

-मुद्रा लोन की सीमा बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गई

-बालिग होने पर सामान्य एनपीएस में बदल जाएगा खाता

पांच राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड और लैंड रजिस्ट्री का एलान

नेचुरल फार्मिंग पर सरकार फोकस एक करोड़ किसानों को जोड़ेंगे

इस बार बजट में महिला, युवा और किसानों पर फोकस रहा। वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए किसानों को बड़ी सौगात दी। उन्होंने एलान किया कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। ग्राम पंचायत इस योजना को लागू करना चाहेंगे वहां बढ़ावा दिया जाएगा। उन्होंने कहा-दालों और तिलहन के उत्पादन को बढ़ावा दे रहे हैं। बजट में सरकार ने नेचुरल फार्मिंग पर जोर दिया है। एक साल में 1 करोड़ किसानों को इससे जोड़ने के लिए योजना का एलान किया गया है। इसके लिए खेती में अनुसंधान, एक्सपर्ट की निगरानी, जलवायु के हिसाब से नई वैरायटी को बढ़ावा दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रदेशों के साथ साझेदारी करके केंद्र सरकार डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने का काम करेगी। 400 जिलों को इसके दायरे में लाया जाएगा। किसानों की जमीन को फार्मर लैंड रजिस्ट्री के तहत लाया जाएगा। पांच और राज्यों में किसान क्रेडिट कार्ड लागू किया जाएगा। आदिवासी समुदायी की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान शुरूआत की जाएगी। यह स्कीम आदिवासी-बहुल गांवों और आकांक्षी जिलों में आदिवासी परिवारों के लिए है।

किसानों के लिए खोला खजाना

- उत्पादकता बढ़ाने और जलवायु के अनुकूल किस्मों के विकास को बढ़ावा देने के लिए कृषि अनुसंधान व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी।
- खेतीबाड़ी के लिए 32 कृषि और बागवानी फसलों की 109 उच्च पैदावार वाली किस्में जारी की जाएगी।
- अगले दो सालों में एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक कृषि के लिए सहायता दी जाएगी, जिसमें सर्टिफिकेट और ब्रांडिंग व्यवस्था रहेगी।
- दस हजार जैव-आदान संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन के लिए एक कार्यनीति बनाई जाएगी।
- सब्जी उत्पादन क्लस्टर विकसित किए जाएंगे। सरकार तीन सालों में किसानों और उनकी जमीन को शामिल करने के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना लागू करेगी।
- डीपीआई का इस्तेमाल करते हुए 400 जिलों में खरीफ का डिजिटल फसल सर्वेक्षण किया जाएगा।
- छह करोड़ किसानों और उनकी जमीन का ब्यौरा को रजिस्ट्री में दर्ज किया जाएगा।
- झींगा ब्रूड-स्टॉक्स के लिए न्यूक्लियस ब्रीडिंग केंद्रों का नेटवर्क स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
- राष्ट्रीय सहकारी नीति लाई जाएगी। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में तेजी आएगी। सरकार ने कृषि और संबद्ध क्षेत्र के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये आवंटन किए हैं।
- सरकार ने बिहार में पर्यटन बढ़ाने के लिए बड़ी घोषणाएं की हैं। महाबोधि मंदिर (बोधगया) और विष्णुपद मंदिर (गया) में काशी विश्वनाथ की तर्ज पर विकास कार्य किया जाएगा। राजगीर और नालंदा में भी पर्यटन पर निवेश की घोषणा की गई है।
- बजट में एमएसएमईएस और विनिर्माण का ध्यान रखा गया है। बजट में बैंक लोन जारी रखने की सुविधा के लिए नई व्यवस्था का एलान किया गया। मुद्रा लोन की सीमा दस लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई है।

हमने विशेष रूप से रोजगार, कौशल प्रशिक्षण, एमएसएमई और मध्यम वर्ग पर ध्यान केंद्रित किया है। पांच वर्ष में 4.1 करोड़ युवाओं को लाभ होगा। जैसा कि अंतरिम बजट में उल्लेख किया गया है, हमें 4 अलग-अलग जातियों गरीब, महिला, युवा और किसान पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। किसानों के लिए हमने सभी प्रमुख फसलों के लिए उच्च न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की है, जो लागत से कम से कम 50 फीसदी मार्जिन के वादे को पूरा करता है।

निर्मला सीतारमण,वित्त मंत्री

ये बजट हमारे स्टार्टअप्स के लिए के लिए ढेर सारे नए अवसर लेकर आया है। इस बजट में नई योजना का ऐलान किया गया है। मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट इकोसिस्टम को हर जिले तक ले जाएंगे। बजट सभी को शक्ति देगा। महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित होगी।

नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

इस बजट में भारत की चमक और महंगाई दर पर कंट्रोल करने की भावना परिलक्षित होती है। खासकर सरकार की जो नौ सूत्रीय योजनाएं प्रस्तुत की गईं। निश्चित रूप से इस बजट के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया में नई पहचान कायम करेगा।

डॉ. मोहन यादव, सीएम, मप्र

किसानों के सशक्तिकरण तथा कृषि के आधुनिकीकरण को समर्पित बजट है। कृषि को टेक्नॉलॉजी आधारित और केमिकल फ्री बनाने के लिए इस बजट में कई कदम उठाए गए हैं। सरकार ने 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ने का लक्ष्य रखा है।

शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय कृषि मंत्री

यह कुर्सी बचाओ बजट है। बजट के जरिए सहयोगियों को खुश करने की कोशिश की गई, जबकि अन्य राज्यों की कीमत पर उनसे खोखले वादे किए। ये बजट कांग्रेस के घोषणापत्र और पिछले बजट का कॉपी पेस्ट है। अडाणी-अंबानी को फायदा लेकिन आम भारतीयों को कोई राहत नहीं।

राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष, लोकसभा

मोदी सरकार का पुराना इतिहास बताता है कि ये 2 करोड़ रोजगार के वादे के साथ सत्ता में आई थी। चार करोड़ रोजगार यानि दोगुना झूठ, डबल इंजन की। अब सरकार इस बजट में चार करोड़ रोजगार की बात कर रही है। यानी यानी डबल इंजन की सरकार अब दोगुना झूठ बोल रही है।

जीतू पटवारी, प्रदेशाध्यक्ष कांग्रेस

किसे-कितनी राशि आवंटित की गई

मंत्रालय	राशि (करोड़ में)
वित्त	1858158.52
रक्षा	621940.85
सड़क	278000.00
रेल	255393.00
उपभोक्ता	223323.36
गृह	219643.31
ग्रामीण	180233.43
रसायन	168499.87
संचार	137293.90
कृषि	132469.86
शिक्षा	120627.87
जल	98713.78
स्वास्थ्य	90958.63
आवास	82576.57
महिला एवं बाल विकास	26092.19
परमाणु ऊर्जा	24968.98
श्रम	22531.47
विदेश	22154.67
सूक्ष्म	22137.95
इलेक्ट्रॉनिक्स	21936.90
ऊर्जा	20502.00
नवीकरणीय	19100.00
विज्ञान	16628.12
पेट्रोलियम	15930.26
सामाजिक न्याय	14225.47
अंतरिक्ष विभाग	13042.75
आदिवासी	13000.00
वाणिज्य	11469.14
भारी उद्योग	7242.00
डेयरी	7137.68
कानून	6788.33
पूर्वोत्तर	5900.00
सांख्यिकी	5453.83
उद्यमिता	4520.00
वस्त्र	4417.03
सूचना	4342.55
आयुष	3712.49
खेल	3442.32
वन	3330.37
खाद्य	3290.00
संस्कृति	3260.93
अल्पसंख्यक	3183.24
पृथ्वी विज्ञान	3064.80
कॉर्पोरेट	2667.06
पर्यटन	2479.62
कार्मिक	2379.87
बंदरगाह	2377.49
नागरिक उड्डयन	2357.14
खान	1941.06
प्रमुख सचिवालय	1884.92
पंचायती राज	1183.64
सहकारिता	1183.39
योजना	837.26
इस्पात	325.66
कोयला	192.55
संसदीय	64.00
कुल योग	**4820512.08**

अहम योजनाएं के लिए बजट

योजनाएं	बजट (करोड़ में)
मनरेगा	86,000
आयुष्मान भारत	7,300
पीएलआई	6,200
सौर ऊर्जा	10,000
पीएम सूर्य	6,250
पीएम आवास (शहरी)	30,171
पीएम आवास (ग्रामीण)	54,500
पीएम विश्वकर्मा	4824
पीएम ग्राम सड़क	19000
मिशन वात्सल्य	1472

बजट देश के आर्थिक विकास में महिलाओं की भूमिका बढ़ाने वाला है। महिलाओं के लिए 3 लाख करोड़ से अधिक का बजट प्रावधान किया गया है। कामकाजी महिला हॉस्टलों और शिशु गृहों की स्थापना कर कामगारों में महिलाओं की अधिक भागीदारी को सुविधाजनक बनाए जाने का प्रयास किया गया है।

-निर्मला भूरिया, मंत्री

यह दिशाहीन सरकार का दृष्टिहीन बजट है। जनता को कोई बुनियादी राहत देने के बजाय झुनझुना पकड़ाया गया है। इनकम टैक्स स्लैब में जो बदलाव किया है, वह नाकाफी है। बढ़ती हुई महंगाई के सामने कुछ भी नहीं है। केंद्र सरकार ने स्थायी नौकरी के बारे में कोई बात नहीं की। किसानों को लेकर बजट में कोई भी सकारात्मक पहल नहीं की है।

-कमलनाथ, पूर्व सीएम

यह बजट किसानों, महिलाओं, गरीबों, युवाओं सहित सभी वर्गों के कल्याण एवं उत्थान पर केंद्रित है। यह बजट मध्यप्रदेश को भी अपने विकास के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने का मौका देगा। विकसित भारत में विकसित मध्यप्रदेश की संभावना छिपी हुई है। इसके लिए केंद्रीय वित्त मंत्री को बधाई देता हूं।

भरतलाल पांडेय, कार्यालय मंत्री, भाजपा

बजट हमारे गावों, गरीबों, किसानों, महिलाओं, युवाओं और जनजातीय वर्ग के कल्याण का है। प्रतिबद्धता से सराबोर और हर व्यक्ति के कल्याण के लिए अत्यंत संवेदनशील सरकार का यह एक दूरगामी व दूरदर्शी विकास बजट है। बजट में विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए मध्यम वर्ग सहित समाज के हर वर्ग को राहत दी है।

-डॉ. विजय शाह, मंत्री

समाज के हर वर्ग और देश को राह दिखाने वाला यह बजट है। यह बजट विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने वाला बजट है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने देश की जो चार जातियां किसान, महिला, युवा और गरीब बताई हैं, यह बजट उनके जीवन में बड़ा परिवर्तन लाएगा। गरीबों का पक्का आवास मिलेगा।

वैभव पंवार, प्रदेशाध्यक्ष, भाजयुमो

किसानों पर फोकस

केंद्रीय बजट 2024 में कृषि और उससे जुड़े सेक्टरों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसके साथ ही छह करोड़ किसानों की जानकारी लैंड रजिस्ट्री पर लाई जाएगी। पांच राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे।

महिलाओं का रखा ख्याल

महिलाओं और लड़कियों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए तीन लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल और शिशु गृह बनाए जाएंगे।

कान्हा- पेंच वन्यजीव गलियाराः बाघ-मानव सहअस्तित्व

संदीप चौकसे
वरिष्ठ परियोजना अधिकारी, सेंट्रल इंडिया लैंडस्केप, डब्लूडब्लूएनफ इंडिया

वन्यजीव गलियारा या वाइल्डलाइफकॉरिडोर, विशेष प्रकार के प्राकृतिक मार्ग जो दो या अधिक प्राकृतिक आवासों या संरक्षित क्षेत्रों को आपस में जोड़ते हैं। वन्यजीवों को बिना किसी बाधा या जोखिम के एक आवास क्षेत्र से दूसरे आवास क्षेत्र में सुरक्षित एवं स्वतंत्र रूप से आवागमन करने में सहायता प्रदान करते हैं। वन्यजीव गलियारों की जैव विविधता को बनाए रखने, जीन प्रवाह को बढ़ाने, और वन्यजीवों के बीच संपर्क स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका है। ये गलियारे वन्यजीवों के लिए भोजन, पानी और प्रजनन के लिए संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित कर उन्हें मानव-जनित बाधाओं से सुरक्षा देने के साथ जैविक संतुलन बनाने एवं जीवों को विलुप्ति के खतरे से बचा कर पारिस्थितिक तंत्र में स्थिरता को बनाये रखने का काम करते हैं।

मध्य प्रदेश के कान्हा टाइगर रिज़र्व (टा.रि.) और पेंच टाइगर रिज़र्व (टा.रि.) की देश भर में अपनी बाघों की संख्या और बेहतर वन्यजीव प्रबंधन के लिए एक अलग ही पहचान है। हाल ही में वर्ष 2022 में हुए देश व्यापी बाघ आंकलन के अनुसार 2074.31 वर्ग कि. मी. में फैले कान्हा टा. रि. एवं 1179.63 वगज़ कि. मी. में फैले पेंच टा. रि. में क्रमशः कुल 105 एवं 77 बाघ हैं।1 इसके अलावा दूसरे बड़े मांसाहारी वन्यप्राणी जैसे की तेंदुए, जंगली कुत्ते, भेड़िये एवं सियार और शाकाहारी वन्यप्राणी जैसे की गौर, सांबर चीतल एवं नीलगाय भी बहुतायत में हैं, इसके अलावा कान्हा में तो मध्य प्रदेश का राजकीय पशु बारासिंघा भी पाया जाता है।

वन्यप्राणियों की इन संरक्षित क्षेत्रों में लगातार बढ़ती संख्या को रहने के लिए ज्यादा जगह, भोजन एवं पानी की आवश्यकता होती है और तो और बाघों का तो अपना अलग इलाका होता है जिसका साझा वो किसी और बाघ से नहीं करते हैं एवं आवास की कमी के कारण इलाके की तलाश में उनके बीच टकराव की स्तिथि निमिज़्त हो जाती है। ऐसी स्थिति में संरक्षित क्षेत्रों के आसपास के वनक्षेत्र वन्यप्राणियों को एक उपयुक्त आश्रय स्थल प्रदान करते हैं, कान्हा एवं पेंच टा. रि. को आपस में जोड़ने वाला वनक्षेत्र इसका एक सटीक उदाहरण है, जिसे हम कान्हा -पेंच वन्यजीव गलियारा/ कॉरिडोर के नाम से जानते हैं।

लगभग 5925 वर्ग कि मी में फैला कान्हा-पेंच कॉरिडोर का वनक्षेत्र मध्य प्रदेश के मंडला, सिवनी और बालाघाट जिले में आता है। सिवनी जिसका अपना एक अलग इतिहास है, सर रुडयार्ड किपलिंग की प्रसिद्ध किताब ''जंगल बुक'' का मुख्य किरदार ''मोगली'' भी सिवनी के जंगलों का ही निवासी था जिसका मुख्य रहवास स्थान कान्हीवाड़ा भी इसी कॉरिडोर का एक भाग है, जहा हिर्री और बैनगंगा नदी के चट्टानी किनारे व झरने देख कर कोई भी जिसने जंगल बुक पढ़ा है, सहज ही इस बात का अंदाजा लगा सकता है। इस कॉरिडोर का ज्यादातर भाग मध्य प्रदेश का सबसे पुराना जिला बालाघाट में समाहित है। जिसमें बैहर तहसील के पठार से लेकर बालाघाट के निचले पहाड़ी ढलान शामिल हैं।

कान्हा-पेंच वन्यजीव गलियारा के वनक्षेत्र में 7 वनप्रभाग समाहित हैं, जिसमें दक्षिण सिवनी, उत्तर एवं दक्षिण बालाघाट और पश्चिम मंडला सामान्य वनमंडल हैं, इसके अलावा बरघाट, लामता और मोहगांव वन मंडल वनविकास निगम के अधिनियत हैं। कॉरिडोर में अधिकांशतः शुष्क पर्णपाती, मिश्रित पर्णपाती और कहीं-कहीं सागौन एवं बांस के सघन वन पाए जाते हैं। यह वनक्षेत्र कई तरह के वन्यप्राणियों का आश्रय स्थल हैं। अखिल भारतीय बाघ आंकलन 2022 में हुई गणना में इस वन्यजीव गलियारा में बाघों की संख्या 97 दर्ज की गयी है, जो पेंच टा. रि. से भी ज्यादा है।

बाघों की यह संख्या इस बात का संकेत है की कॉरिडोर के घने जंगल बाघों को रहने के लिए एक उपयुक्त आवास तो प्रदान कर ही रहें हैं, साथ ही इन जंगलों में बाघों के भोजन, शाकाहारी

वन्यप्राणियों की भी प्रचुरता है। कॉरिडोर में बढ़ती बाघों एवं अन्य वन्यजीवों की यह संख्या खुशी के साथ-साथ चिंता का भी विषय है। कॉरिडोर एवं इसके आसपास के इलाकों में लगभग 715 गांव स्थित हैं, जिनमें काफी संख्या में मानव आबादी निवास करती है, 2 और ये स्थानीय लोग प्रत्यक्ष् और अप्रत्यक्ष रूप से अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए जंगलों से जुड़े हुए हैं, जिससे अकसर वन्यजीवों एवं मनुष्य के बीच आपसी टकराव बना रहता है। बाघ और दूसरे मांसाहारी वन्यप्राणी अकसर गांव वालों के पालतू मवेशियों को मार देते हैं, कभी-कभी तो ये मनुष्यों पर भी हमला कर देते हैं।

इस तरह की घटनाएं बाघ एवं मनुष्यों के बीच आपसी संघर्ष पैदा करती हैं। मध्य प्रदेश वनविभाग के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018 से 2022 तक पांच वर्षों में इस कॉरिडोर में मांसाहारी वन्यप्राणियों द्वारा लगभग 6376 मवेशी मारे गए हैं (तालिका 1)। 3 और हर वषज़ बाघों की संख्या बढ़ने के साथ-साथ यह आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। इसी तरह 355 जन घायल और 17 जनहानि की घटनायें हुई हैं, और यह घटनायें निरंतर बढ़ती जा रही हैं।3 साल 2023 में सितम्बर से नवंबर के बीच तीन माह में ही बाघों द्वारा 6 मौते दर्ज की गयी थी। इन बढ़ती घटनाओं से यहाँ के निवासियों में वन्यजीवों एवं वनविभाग के प्रति नकारात्मकता की भावना बढ़ती है, और गांव वाले कभी-कभी हिंसात्मक भी हो जाते हैं। कभी-कभी तो बाघों और तेंदुओं द्वारा मारे गए मवेशियों के शवों में जहर मिला दिया जाता है, जिससे उनको खाने वालेवन्यप्राणियों को भारी नुकसान पहुँचता है। हालांकि बाघों की इतनी संख्या होने के बाद भी कान्हा-पेंच वन्यजीव गलियारा में इस तरह की नकारात्मक घटनाएं कम ही सामने आयी हैं, इसका कारण शायद स्थानीय निवासियों की बाघों एवं वन्यजीवों के प्रति श्रद्धा, सहनशीलता और धामिज़्क मान्यताएं हैं, जो मानती हैं, की अगर जंगल में बाघ है, तो प्रकृति का संतुलन बना रहेगा और लोग सुरक्षित रहेंगे।

कान्हा-पेंच वन्यजीव गलियारा में मानव-बाघ द्वन्द एक चिंता का विषय है, जो भविष्य में एक विकराल रूप ले सकता है। मध्य प्रदेश वन विभाग इन नकारात्मक परिस्थितियों से निपटने के लिए हरसंभव प्रयासरत है। बाघों या अन्य मांसाहारी वन्यप्राणी द्वारा किसी मवेशी के मारे जाने पर वन विभाग द्वारा मवेशी मालिक को मुआवजे की व्यवस्था की गयी है। जिसमें वन्यप्राणी द्वारा मवेशी के मारे जाने पर अधिकतम 30000 रुपए तक प्रदाय किये जाते हैं। इसके अलावा वन्यप्राणी द्वारा किसी व्यक्ति के मारे जाने पर रु. 8 लाख एवं घायल को रु. 50 हजार से रु. 2 लाख तक की राशि मुआवजे के तौर पर दी जाती है। वन्यप्राणी संरक्षण में कार्य करने वाली संस्था डब्लू डब्लूएपफ़-इंडिया भी इस कॉरिडोर में मानव-बाघ द्वन्द (मानव-वन्यप्राणी संघर्ष) को कम करने के लिए प्रयासरत है। डब्लू डब्लूएफ़-इंडिया ने वर्ष 2010 में इस कॉरिडोर में IRS, इंटरिम रिलीफ स्कीम (आई.आर.एस) की शुरआत की थी। जिसके अंतगज़्त वन्यप्राणी द्वारा किसी मवेशी के मारे जाने पर मवेशी मालिक को संस्था के द्वारा रु. 1200 की त्वरित आथिज़्क सहायता प्रदाय की जाती है, ताकि तत्काल उनके आथिज़्क नुकसान की कुछ भरपाई हो सके और उनकी नाराजगी और गुस्से को कुछ हद तक कम किया जा सके। इसके अलावा संस्था के प्रतिनिधियों द्वारा जंगल में ट्रैप कैमरा लगाकर बाघों की गतिविधि पर भी नजर रखी जाती है, अगर बाघ या अन्य जानवर गांव या आबादी के आसपास देखे जाते हैं तो वनविभाग को सूचित कर दिया जाता है, जिससे स्थानीय लोगों को सावधान किया जा सके और किसी अप्रत्याशित घटना को रोका जा सके।

जलवायु संकटः अगले 20 सालों में स्थानीय प्रजातियों की विविधता में 39 फीसदी की कमी के आसार

शोधकर्ताओं द्वारा बनाया गया एक नया मॉडल जलवायु में बदलाव के कारण विलुप्त होने की कगार में पड़ी स्थलीय और समुद्री प्रजातियों के अनुपात का फिर से जांच पड़ताल करता है। वहीं पारंपरिक मॉडलों के पूर्वानुमान इस बात की तस्दीक करते हैं कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में स्थानीय प्रजातियों की विविधता 2041-2060 के बीच 54 फीसदी तक कम हो सकती है। जबकि नया मॉडल 39 फीसदी की कमी का पूर्वानुमान लगाता है। हालांकि यह अनुपात भी चिंताजनक है, शोधकर्ताओं का कहना है कि जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता पर इसके प्रभाव को कम करने के लिए तत्काल उपाय किए जाने चाहिए।

इफ्रेमर और लॉजेन विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं की अगुवाई में किया गया यह शोध नेचर इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन पत्रिका में प्रकाशित किया गया है।

धरती पर तापमान जहां अंटार्कटिका में लगभग -70 डिग्री सेल्सियस से लेकर भूमध्य रेखा पर +48 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तक अलग-अलग होता है। हमारी धरती पर वर्तमान में मौजूद ये जलवायु सीमाएं हमेशा विकसित हुई हैं। उदाहरण के लिए, 1,30,000 साल पहले, अंतिम इंटर-ग्लेशियल अवधि के दौरान, जलवायु गर्म थी और सदी के अंत तक हम उम्मीद कर सकते हैं कि यह उसके समान रही होगी।

इसलिए इस अवधि के दौरान विकसित होने वाली प्रजातियां आने वाले बदलावों के लिए पहले से अनुकूलित हो सकती हैं। हालांकि, अब तक, जलवायु परिवतज़्न के लिए प्रजातियों की प्रतिक्रिया की भविष्यवाणी करने वाले सांख्यिकीय मॉडल ने इस संभावित पूवज़्-अनुकूलन को ध्यान में नहीं रखा, जिससे पूवानज़्मान गलत हो सकते हैं।

शोधकर्ता ने शोध के हवाले से कहा कि उष्णकटिबंधीय समुद्री या स्थलीय प्रजातियों का उदाहरण लें तो पारंपरिक सांख्यिकीय मॉडल पूर्वानुमान लगाते हैं कि यह उन जगहों पर गायब हो जाएगी जहां तापमान 48 डिग्री सेल्सियस की वर्तमान गर्म सीमा से अधिक है।

क्या यह प्रजाति 50 डिग्री सेल्सियस के वायु तापमान के साथ रह सकती है? या गर्म या नमकीन पानी में? जलवायु परिवर्तन के प्रभाव में, ऐसी परिस्थितियां फिर से सामने आ सकती हैं और कुछ प्रजातियों के जलवायु क्षेत्र के विस्तार को जन्म दे सकती हैं।

जब कोई प्रजाति जलवायु परिस्थितियों से 'चिह्नित' होती है, तो वह इन परिस्थितियों के प्रति पूर्व-अनुकूलन बनाए रखती है जो हजारों या लाखों वर्षों तक चल सकता है। यदि उसका आवास ऐसी जलवायु के अनुकूल विकसित होता है जिसका अनुभव प्रजाति पहले ही कर चुकी है, तो यह पूर्व-अनुकूलन उसे इन नई जलवायु परिस्थितियों के प्रति सहनशीलता प्रदान करेगा। फ्रेमर और लॉजेन विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने अपने मॉडल को दुनिया भर से लगभग 25,000 स्थलीय और समुद्री प्रजातियों, जिसमें जानवर और पौधे भी शामिल हैं पर आजमाया, जिसके लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (आईयूसीएन) भौगोलिक वितरण मानचित्र प्रदान करता है।

भविष्य के जलवायु परिवर्तन (आईपीसीसी व सीएमआईपी5) के परिदृश्यों के साथ अपने मॉडल में इस आंकड़े को जोड़कर, उन्होंने पाया कि इनमें से 49 फीसदी प्रजातियां वर्तमान में जलवायु स्थितियों की सीमाओं से सटे जलवायु के ऐसे स्थानों में रहती हैं और उनमें से 86 फीसदी का स्थान हो सकता है वर्तमान जलवायु सीमाओं से परे हो। समुद्री प्रजातियों के लिए यह आंकड़ा बढ़कर 92 फीसदी हो जाता है।

सबसे अनोखे परिणाम स्थलीय और समुद्री प्रजातियों के लिए उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से संबंधित है। यह स्वीकार किया जाता है कि जलवायु परिवर्तन से इन क्षेत्रों में जैव विविधता का भारी नुकसान होगा, पारंपरिक मॉडलों के अनुसार 2041-2060 तक उष्णकटिबंधीय स्थलीय प्रजातियों का 54 फीसदी तक नुकसान होगा। जबकि हमारा मॉडल प्रजातियों की विविधता में 'केवल' 39 फीसदी की कमी का पूवार्नुमान लगता है।

शोधकर्ता ने शोध में कहा, हमारे मॉडलों को लगातार अपडेट करना और कुछ प्रजातियों की संभावित प्रतिक्रिया के बारे में नई परिकल्पनाएं विकसित करना महत्वपूर्ण है। यह संभावना है कि उष्णकटिबंधीय प्रजातियां पहले की तुलना में जलवायु परिवर्तन को बेहतर तरीके से सहन कर सकती हैं, तो पुराने अनुमान ठंडे, अल्पाइन और ध्रुवीय क्षेत्रों में प्रजातियों के लिए और काफी हद तक समशीतोष्ण क्षेत्रों में प्रजातियों के लिए मान्य हैं। इसलिए की वर्तमान में इन क्षेत्रों में जो जलवायु है वह 2041 तक मौजूद नहीं रहेगी। ये प्रजातियां पहले से ही अपने जलवायु क्षेत्र की सीमा के बाहर रह रही हैं और वे काफी गर्म तापमान को सहन नहीं कर पाएंगी।

ग्लेशियरों के पिघलने से प्राकृतिक आपदाओं की जद में हैं पहाड़ी इलाके

केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कहा है कि सरकार ने जलवायु परिवर्तन के कारण ग्लेशियरों के पिघलने को गंभीरता से लिया है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (एमओईएस), विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी), विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के माध्यम से वित्त पोषित कई भारतीय संस्थानों, विश्वविद्यालयों और संगठनों के माध्यम से ग्लेशियरों, जिनमें ग्लेशियरों का पिघलना भी शामिल है, पर विभिन्न वैज्ञानिक अध्ययन किए गए हैं।

हिमाचल प्रदेश के चंद्रा बेसिन में छह ग्लेशियरों की निगरानी राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र (एनसीपीओआर) द्वारा की जाती है, जो कि एमओईएस के तहत एक स्वायत्त संस्थान है। ताकि ग्लेशियरों की जलवायु परिवर्तन के प्रति अलग-अलग प्रतिक्रिया और नीचे की ओर बहने वाले जल विज्ञान पर इसके प्रभाव को समझा जा सके। एनसीपीओआर द्वारा किए गए एक अध्ययन से पता चलता है कि चंद्रा बेसिन की दो प्रमुख ग्लेशियल झीलों (समुद्र टापू और गेपांग गथ) ने पिछले पांच दशकों (1971-2022) में इस क्षेत्र और मात्रा में पर्याप्त विस्तार देखा जा रहा है, जो ग्लेशियर से बनी झील के फटने से आने वाली बाढ़ के लिए उनके खतरे की आशंका के लिए अहम है। डीएसटी के स्वायत्त संस्थान वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी द्वारा किए गए अध्ययनों से उत्तराखंड के ग्लेशियर और पेरी-ग्लेशियल क्षेत्रों में सिकुड़ते ग्लेशियरों और अन्य प्रक्रियाओं से संबंधित खतरों में वृद्धि की जानकारी है। इन खतरों में ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड, मलबे का प्रवाह और मोरेन विफलताएं शामिल हैं। विज्ञप्ति में कहा गया है है डीएसटी ने ग्लेशियरों के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के लिए अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को भी वित्त पोषित किया है। बेंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्थान जलवायु परिवर्तन के लिए दिवेचा केंद्र मौजूदा और संभावित ग्लेशियर झीलों का मानचित्रण कर रहा है। यह सिक्किम और उत्तराखंड में कई ऐसे स्थलों की पहचान कर रहा है जिसके कारण यहां अचानक बाढ़ आ सकती हैं। इसके अलावा डीएसटी ने हिमालयी क्रायोस्फीयर पर एक नेटवर्क कार्यक्रम स्थापित किया है, जो राष्ट्रीय सतत हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र मिशन के तहत ग्लेशियर अनुसंधान के विभिन्न विषयों पर क्षेत्र आधारित छह परियोजनाओं का समर्थन करता है। विज्ञप्ति के अनुसार, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय ने वर्ष 2023 में रुड़की के राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान (एनआईएच) में क्रायोस्फीयर और जलवायु परिवर्तन अध्ययन केंद्र की स्थापना की है, ताकि भविष्य में जल उपलब्धता की चिंता को दूर करने के लिए देश में बर्फ और ग्लेशियर संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन की सुविधा मिल सके।

समृद्ध मप्र के लिए प्राकृतिक खेती का विस्तार

समृद्ध मप्र के लिए प्राकृतिक खेती का विस्तार, समृद्ध मप्र के लिए प्राकृतिक

मंडला का सिंहपुर गांव पूरी तरह रसायन-मुक्त

मंडला। जागत गांव हमार

मध्यप्रदेश में भारत और जर्मनी के सहयोग से हरित सतत विकास भागीदारी कार्यक्रम में चल रही 16 परियोजनाओं में संवहनीय खेती अपनाकर पंचायतें कृषि के क्षेत्र में तेजी से आत्म-निर्भर बन रहीं हैं। आत्मनिर्भर पंचायत-समृद्ध मध्यप्रदेश पर आयोजित तीन दिवसीय कार्यशाला में जनजातीय जिलों की पंचायतों से आई कृषक महिलाओं ने उत्साह से अपनी उपलब्धियां बताई। इसका आयोजन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग और जर्मन संस्था जीआईजेड द्वारा किया गया। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रह्लाद सिंह पटेल के उत्साहवर्धन पर जनजातीय महिलाओं ने विस्तार से आत्मनिर्भर खेती पर चर्चा की। मंडला जिले के ग्राम पंचायत कांसखेड़ा की कृषक दीदी रेखा ने गाय, गोबर और गौमूत्र आधारित खेती की जानकारी दी। जलवायु परिवर्तन के खतरो का मध्यप्रदेश कैसे सामना कर समृद्ध हो सकता है इसकी रणनीति पर निरंतर विचार चल रहा है। विभिन्न पंचायतों में चल रहे आदर्श कार्यों की स्थानीय ग्रामीण जनजातीय महिलाओं ने विस्तार से जानकारी दी। मंडला के निवास विकासखंड में सिंहपुर गांव की रहने वाली लक्ष्मी बैरागी ने बताया कि कैसे सिंहपुर गांव रासायनिक खेती से मुक्त गांव बन गया है। यहां पूरी तरह से प्राकृतिक खेती हो रही है। यहां 450 एकड़ जमीन है जो 120 किसानों की है और 80 एकड़ आवासीय भूमि है। यहां 12 एकड़ में प्लांटेशन लगा है और 45 एकड़ में चारा उगाया जा रहा है। वे कहती है कि जल, जंगल जमीन, पशु और चारागाह के बिना प्राकृतिक खेती नहीं की जा सकती। प्राकृतिक खेती करने से गोमूत्र आधारित कीटनाशक और अन्य खाद की कमी पड़ जाती है। इसलिए गौमूत्र से जैविक खाद और कीटनाशक बनाने का काम पशु शेड से जुड़कर किया जा रहा है।

दीदियों ने घरों में किचन गार्डन बनाया

मंडला जिले की ही बिछिया विकासखंड के कन्हरी बजन ग्राम पंचायत के भुलूज गांव की रहने वाली किसान दीदी ने बताया कि कैसे तालाबों में मछली पालन किया जा रहा है। कैसे मुर्गी पालन और पशु शेड का उपयोग जैविक खाद बनाने में हो रहा है। इस गांव में 65 किसान दीदियों ने अपने घरों में किचन गार्डन विकसित किया है और सब्जियां उगा रही हैं। आंगनबाड़ियों को भी सब्जियां दे रही हैं। पूरा गांव प्राकृतिक खेती कर रहा है। यहां के किसान खेती में लगने वाले महंगे रसायनों से मुक्त होकर अब खेती में आत्मनिर्भर बन रहे हैं। मोहगांव विकासखंड की ग्राम पंचायत कावरडोंगरी की किसान दीदी बताती हैं कि पोषण वाटिका के पहले सब्जियों के लिए बाजार जाते थे और रसायन वाली सब्जियां खाते थे। अब शुद्ध सब्जियां मिल रही हैं। जिला पंचायत सागर के अध्यक्ष हीरा सिंह राजपूत, शाजापुर जिला पंचायत की अध्यक्ष नेहा यादव, जिला पंचायत सतना के अध्यक्ष रामचंद्र कोली ने भी अपने विचार रखे। स्वचालित जीवामृत उत्पादन संयंत्र, प्लांट क्लीनिक और सामुदायिक जैव संसाधन केंद्र के मॉडल की भी जानकारी दी गई। प्लांट क्लीनिक सागर के बंडा में चल रहा है। किसानों को पौधों में लगने वाले रोगों और रोकथाम के बारे में जानकारी दी जाती है।

वर्मी कंपोस्ट बनाने के चार टैंक

मंडला के गांव चंदाटोला में जीवामृत जैविक खाद और गौमूत्र से तैयार किए जा रहे हैं कीटनाशक बन रहे हैं। यहां की चंपा दीदी कहती हैं कि एक बार में 2000 लीटर जीवामृत बन जाता है। कोई मेहनत भी नहीं लगती। प्रेमवती बाई बताती हैं कि 10 किलो बेसन, 10 किलो गुड़, 50 लीटर गोमूत्र और 50 किलो गोबर के मिश्रण से कीटनाशक तैयार होता है। आसपास के चार-पांच गांवों में किसानों को बेच देते हैं। अब तक 7200 लीटर बेचने से 45 हज़ार का शुद्ध मुनाफा हुआ। सागर जिले के शासन गांव की मनीषा दीदी बताती है कि वर्मी कंपोस्ट बनाने का काम शुरू किया है। चार टैंक तैयार किए गए हैं और 10 गांव में सप्लाई कर 20 हजार का फायदा हो चुका है।

पात्रता एप

ग्वालियर के जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी विवेक शर्मा ने पात्रता एप के बारे में जानकारी दी। इसका उपयोग कर योजनाओं का लाभ लेने की पात्रता और जरूरी दस्तावेज की जानकारी मिल जाती है।

डायबिटिक मरीजों के लिए चावल की खेती पर मप्र में होगा अनुसंधान

जबलपुर। जागत गांव हमार

अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान (आईआरआरआई) फिलिपीन्स एवं जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के संयुक्त तत्वावधान में एक कृषि वैज्ञानिकों की चावल अनुसंधान के कार्य के लिए तीन दिवसीय कार्यशाला आयोजित हुई, जिसके मुख्य अतिथि प्रो पी के मिश्रा, कुलपति जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर रहे। जिन्होने बताया कि इस परियोजना से मध्य प्रदेश के असिंचित क्षेत्र में भी चावल के उत्पादन का रकबा बढ़ेगा। आई आर आर आई से आए प्रमुख वैज्ञानिक डा जौहर अली बैठक में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे। कार्यक्रम में आई आर आर आई की महानिदेशक डॉ पिंटो ने भी ऑनलाइन जुड़कर परियोजना के विषय में जानकारी प्रदान की। इस परियोजना में असिंचित क्षेत्र के लिए उन्नत प्रजातियों का विकास और बायो फोर्टीफाईड प्रजातियों के साथ-साथ डायबिटिक मरीजों को खाने के लिए पोषण से भरपूर प्रजातियों की खेती के लिए अनुसंधान होगा। कृषि महाविद्यालय रीवा से इस कार्यक्रम के लिए विशेष रूप से अधिष्ठाता डॉ एस के त्रिपाठी एवं प्रमुख वैज्ञानिक डॉ आर के तिवारी को आमंत्रित किया गया था। जिन्होंने बताया कि इस मेगा प्रोजेक्ट में रीवा संभाग के साथ-साथ इसके आसपास चावल क्षेत्र में पाए जाने वाली लोकल प्रजातियों पर अनुसंधान कार्य कर उन्हें उन्नत बनाया जाएगा साथ साथ धान की सीधी बुवाई के लिए कार्य होगा, जिससे समय और पानी की बचत होगी। इस कार्यक्रम में डीन फैकल्टी डा धीरेन्द्र खरे, निदेशक अनुसंधान सेवाए डॉ जी के कोतू , निदेशक विस्तार सेवाएं डॉ डी पी शर्मा, निदेशक डा मोनी थॉमस, डीन जबलपुर डॉ आशुतोष श्रीवास्तव, डी एस डब्ल्यू डॉ अमित शर्मा, विभागाध्यक्ष डॉ एस दास, डॉ एस के पांडेय एवं प्रो एच के राय के साथ साथ प्राध्यापकगण, वैज्ञानिक एवं प्रगतिशील कृषकों ने भाग लिए।

-गड़बड़ी की तो वेयर हाउस संचालक, अधिकारियों पर गिरेगी गाज

राज्य स्तरीय दल करेगा भंडारित मूंग-उडद की गुणवत्ता की जांच

भोपाल। जागत गांव हमार

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत ने निर्देश दिए हैं कि उपार्जन की हुई मूंग निर्धारित मानकों से खराब गुणवत्ता की पाये जाने एवं ई-उपार्जन पोर्टल पर दर्ज मात्रा से भिन्न पाए जाने पर संबंधित वेयर हाउस संचालक और जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री की मंशानुसार विभाग किसानों के हितों का पूरी तरह से संरक्षण करे। राजपूत ने यह निर्देश मंत्रालय में विभागीय योजनाओं की समीक्षा के दौरान दिए। मूंग और उड़द के भंडारण में किसी भी प्रकार की गुणवत्ता में कमी को रोकने के लिए मंत्री ने संबंधित विभागों से समन्वय कर राज्य स्तरीय दल बनाने और जांच करने के निर्देश दिए। मूंग उपार्जन वाले जिलों में राज्य स्तरीय जांच दल बनाकर भेजें तथा

गोदामों में भंडारित मूंग-उड़द की गुणवत्ता और मात्रा की जांच कराएं। मंत्री ने कहा कि मुझे शिकायतें प्राप्त हो रही है कि जिन जिलों में उपार्जन का कार्य किया जा रहा है, वहां पहले से ही मूंग एवं उड़द भंडारित कर रख ली गई है। जबकि किसानों से उपार्जन होने के बाद ही निर्धारित मानकों के अनुसार पैंकिंग की गई उपज का भंडारण किया जाना है। किसी भी जिले में उपार्जन और भंडारण में कमी न आये तथा किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी उपार्जन में न उठानी पड़े। मंत्री ने मैदानी स्तर तक व्यवस्था ठीक करने के निर्देश दिए हैं।

उपभोक्ता को परेशानी नहीं हो

मंत्री ने कहा कि सभी पात्र हितग्राहियों को उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित करें। उपभोक्ता के राशन का यदि बायोमैट्रिक नहीं है तो आधार से जुड़े मोबाइल में ओटीपी के माध्यम से भी खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाए। इसके अतिरिक्त बुजुर्ग उपभोक्ता द्वारा नामिनी बनाए गए व्यक्ति को भी खाद्यान्न दिया जा सकता है। इन सुविधाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। उपभोक्ताओं के मोबाइल में इस संबंध में मैसेज भी करें। किसी भी हालत में उपभोक्ता को परेशानी नहीं होनी चाहिए। जो उपभोक्ता लगातार 6 महीने से राशन नहीं ले रहे हैं उनके नाम राशन दुकान के बाहर चस्पा करें। जिससे वह या उनके परिचित जान सके इसके बाद भी यदि उपभोक्ता नहीं आते हैं तो उनका नाम सूची से हटाने की कार्रवाई की जाए।

-सेंसर और रिमोट से सिंचाई और फसल की होगी निगरानी

स्मार्ट हॉर्टिकल्चर टेक्नोलॉजी से सब्जी-बागवानी में मिलेगी बंपर उपज, किसानों को होगा फायदा

भोपाल।

भारत के अलग-अलग राज्यों में स्मार्ट हॉर्टिकल्चर टेक्नोलॉजी का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। इस तकनीक के उपयोग से कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी हो रही है। किसान अब इस तकनीक के महत्व को समझने लगे हैं और इसे अपनाकर अपने खेतों में बेहतर रिजल्ट पा रहे हैं। स्मार्ट हॉर्टिकल्चर टेक्नोलॉजी का तात्पर्य उन उन्नत तकनीकों से है जो खेती और बागवानी को अधिक प्रभावी और उत्पादक बनाने में सहायक होती है। इसमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स, सेंसर्स, ड्रोन्स, रोबोटिक्स और डेटा एनालिटिक्स जैसी तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। डॉ. राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, समस्तीपुर, बिहार के प्रोफेसर और प्रधान अन्वेषक, अखिल भारतीय फल अनुसंधान परियोजना के डॉ. एसके सिंह के अनुसार, स्मार्ट हॉर्टिकल्चर टेक्नोलॉजी में सेंसर का उपयोग करके तापमान, आर्द्रता, प्रकाश की तीव्रता, मिट्टी की नमी और पोषक तत्वों के स्तर जैसी पर्यावरणीय स्थितियों का वास्तविक डेटा एकत्र किया जाता है। यह पौधों के विकास की निगरानी और प्रबंधन में मदद करता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स विभिन्न उपकरणों और घटकों की कनेक्टिविटी को सक्षम बनाती है, जिससे डेटा विनिमय और उपकरणों के रिमोट कंट्रोल की सुविधा मिलती है। स्वचालित सिंचाई सिस्टम सेंसर और मौसम डेटा का उपयोग करके पौधों की पानी की जरूरतों को निर्धारित करते हैं, जिससे पौधों को सही समय पर और सही मात्रा में पानी मिलता है।

समस्या का पहले संकेत

डॉ. एसके सिंह के अनुसार, एआई और मशीन लर्निंग सिस्टम के माध्यम से पौधों के स्वास्थ्य, विकास पैटर्न और रोग एवं कीट का पता लगाने के बारे में पहले ही अवलोकन कर लेता है। भविष्यवाणियां प्रदान करता है। इस तकनीक से किसान कीट रोग और परेशानियों से समय रहते छुटकारा पाने के लिए सक्रिय निर्णय ले सकते हैं। वर्टिकल सिस्टम खेती में पौधों को खड़ी परतों या संरचनाओं में उगाया जाता है, जिससे कम जगह में ज्यादा उपज मिलती है। इसमें एलईडी लाइटिंग, हाइड्रोपोनिक्स और स्वचालित पोषक तत्व वितरण प्रणाली जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग किया जाता है।

दूर से भी खेत की निगरानी

रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम के माध्यम से किसान अपने खेतों की निगरानी और नियंत्रण दूर से कर सकते हैं। मोबाइल एप्लिकेशन या वेब आधारित प्लेटफार्मों के माध्यम से वास्तविक समय डेटा तक पहुंच सकते हैं। पर्यावरणीय मापदंडों को समायोजित कर सकते हैं और गंभीर स्थितियों या सिस्टम विफलताओं के बारे में अलर्ट या सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। डेटा एनालिटिक्स के माध्यम से खेती संबंधित निर्णय लेने में सहायता मिलती है. यह संसाधन आवंटन को अनुकूलित करने और समग्र उत्पादकता में सुधार करने के लिए पैटर्न, रुझान और सहसंबंधों की पहचान करता है।

मोबाइल एप्लिकेशन से कई काम आसान

सब्जी और बागवानी में रोबोटिक सिस्टम का उपयोग करके रोपण, कटाई, छंटाई और फसल के रखरखाव जैसे काम किए जाते हैं। यह सिस्टम श्रम जरूरतों को कम करते हैं और दक्षता को बढ़ाते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों, ऊर्जा-कुशल प्रकाश व्यवस्था और स्मार्ट पावर प्रबंधन तकनीकों का उपयोग करके ऊर्जा खपत को अनुकूलित किया जाता है। मोबाइल एप्लिकेशन से किसान अपनी बागवानी प्रणालियों की निगरानी और नियंत्रण के लिए उपयोगकर्ता के अनुकूल इंटरफेस का उपयोग कर सकते हैं।

टेक्नोलॉजी से लाएं क्रांति

स्मार्ट हॉर्टिकल्चर टेक्नोलॉजी से पर्यावरणीय कारकों की निगरानी और नियंत्रण करने से उत्पादकता में वृद्धि होती है। उच्च गुणवत्ता युक्त उत्पाद प्राप्त होते हैं। सेंसर और स्वचालन प्रणाली का उपयोग करके संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग किया जाता है, जिससे अपशिष्ट को कम किया जाता है और लागत बचत होती है। वास्तविक समय डेटा और अंतर्दृष्टि के आधार पर समय पर निर्णय लेने की सुविधा मिलती है। कुल मिलाकर स्मार्ट हॉर्टिकल्चर कृषि में उत्पादकता, संसाधन दक्षता, स्थिरता और निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाता है। प्रौद्योगिकी और डेटा-संचालित दृष्टिकोणों के संयोजन से यह कृषि पद्धतियों में क्रांति लाने और अधिक कुशल और टिकाऊ खाद्य उत्पादन प्रणाली में योगदान करने की क्षमता रखता है।

-पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रह्लाद सिंह पटेल का आह्वान

पंचायत प्रतिनिधि एक गांव को आदर्श बनाने की लें जिम्मेदारी

भोपाल। जागत गांव हमार

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रह्लाद सिंह पटेल ने सभी स्तरों की पंचायतों के पदाधिकारियों का आह्वान किया है कि वे अपनी पसंद के किसी एक गांव को आदर्श गांव बनाने के लिए सभी उपलब्ध संसाधनों और विभिन्न योजनाओं में आपसी समन्वय के साथ एक मॉडल विलेज बनाएं। उन्होंने कहा कि अपने सपनों का गांव बनाने की शुरुआत करें। दरअसल, मंत्री यहां आत्मनिर्भर पंचायत- समृद्ध मध्यप्रदेश विषय पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग और जर्मन संस्था जीआईजेड द्वारा आयोजित कार्यशाला के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जो पंचायतें शहरों से से लगी हैं उनकी अपनी समस्याएं और मुददे होते हैं। वे अर्ध-शहरी कहलाती हैं। ऐसी 1200 पंचायतें हैं। इनके अध्यक्षों, उपाध्यक्षों, सदस्यों और अधिकारियों के साथ भी जल्दी ही चर्चा की जाएगी। इसी प्रकार पेसा पंचायतों और वन संरक्षित क्षेत्रों के समीप स्थित पंचायतों की स्थिति सामान्य पंचायतों से भिन्न है। उनके मुददों पर भी चर्चा की जाएगी।

स्थान का करें चयन

पटेल ने कहा जिन पंचायतों की जनसंख्या 5000 से ज्यादा है वहां दो सामुदायिक भवन बनाए जाएंगे। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि वे उचित निर्माण स्थल का चयन करने की कार्रवाई शुरू कर दें। उन्होंने कहा कि जिला पंचायतों के पदाधिकारी जनपद पंचायतों की बैठकों में परामर्शदाता की भूमिका निभा सकते हैं लेकिन निर्णय प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करें। सभी पंचायतों के पदाधिकारी बैठकों के नियम की जानकारी रखें। इससे टकराव नहीं होगा। पंचायतों में की जा रही विकास की गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखें ताकि समय पर उनमें सुधार हो सके।

बैठकों को गंभीरता से लें

मंत्री ने कहा कि पंचायत प्रतिनिधि सामाजिक रूप से जिम्मेदार व्यक्ति होते हैं। उन्हें पूरी मेहनत से अपनी जिम्मेदारी निभाना करना चाहिए। पंचायतों की सामान्य सभा की बैठकें कैबिनेट की बैठक के समान होती हैं। इसको पूरी गंभीरता से लें। जहां बैठकें नहीं हुई है वहां पर निश्चित अंतराल में इन बैठकों का आयोजन करें। यह सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। पंचायतों में उपलब्ध धनराशि चुने हुए पंचायत प्रतिनिधियों की सहमति से ही खर्च होगी।

सुझावों पर होगा विचार

मंत्री नें पंचायत पदाधिकारियों का आह्वान किया कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनकी पंचायतों में हुए विकास कार्यों का उपयोगिता प्रमाणपत्र तत्काल प्रस्तुत कर दिया जाए। हमेशा व्यवस्थाओं में सुधार लाने के दृष्टिकोण के साथ ही काम करें। कार्यशाला में दिए गए सभी सुझावों पर विचार होगा और उपयुक्त निर्णय लिए जाएंगे। वित्तीय अनुशासन का पालन करना जरूरी है। कई केन्द्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन में पंचायतों की सजगता से मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय स्तर पर नाम हुआ है।

कहीं सर्वेयरों कर रहे तंग तो कहीं वारदाने नहीं होने से रुकी है खरीदी

समर्थन मूल्य पर मूंग बेचने वाले किसानों को खरीदी केंद्रों पर चबाने पड़ नाकों चने

डा. बृजेश शर्मा, नरसिंहपुर। जागत गांव हमार

सरकार को समर्थन मूल्य पर मूंग देने के लिए किसानों को नाकों चने चबाना पड़ रहे हैं । कहीं उन्हें सर्वेयरों की जेब गर्म करना पड़ रही है तो कहीं-कहीं कई दिनों तक ट्रैक्टरों में अनाज भरकर मंडी या वेयरहाउस में वक्त गुजारना पड़ रहा है । कहीं वारदाने नहीं है । जिससे उन्हें अपने अनाज को बेचने का इंतजार करना पड़ रहा है। कहीं अनाज का पैसा एक-एक माह गुजर जाने के बावजूद नहीं मिला है। पूरे मध्यप्रदेश में ग्रीष्मकालीन मूंग खरीदी का अंतिम दौर है। हर जगह किसान सरकार की ढुलमुल नीतियों और केंद्र की व्यवस्थाओं से दो-चार हो रहा है । इसकी कुछ बानगी प्रदेश के दो बड़े खेतीबाड़ी वाले जिलों में आसानी से देखकर समझा जा सकता है कि किस तरह किसान व्यवस्थाओं से परेशान है । प्रदेश में अच्छी खेती-बाड़ी करने वाले जिलों में विदिशा और नरसिंहपुर शामिल हैं ।

पहले विदिशा जिले की बात करें तो लोगों को याद होगा कि एक हफ्ते पहले ही नरसिंहपुर जिले के पड़ोसी जिले रायसेन में राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने मूंग खरीदी केंद्र का जायजा लिया था और खरीदी केंद्र पर अवैध वसूली की शिकायत पर जमकर अधिकारियों की क्लास भी ली थी लेकिन विदिशा जिले में ऐसा किसी भी जनप्रतिनिधि ने नहीं किया जिसका फायदा उठाते हुए मूंग खरीदी केंद्र के जिम्मेदारों की सहमति से सवेज़्यर के द्वारा विदिशा जिला मुख्यालय की पुरानी उपज मंडी स्थित गोदाम क्रमांक 2 में सर्वेयर द्वारा हर एक किसान से 300 रु प्रति क्विंटल के हिसाब से वसूली करता दिखा इसके बाद ही खरीदी की जा रही है।

ऐसा कुछ आरोप मूंग की उपज तुलाने उपार्जन केंद्र पर पहुंचे किसान बाबू सिंह राजपूत ने लगाए

बाबू सिंह राजपूत ने एक वीडियो साझा करते हुए पैसे के लेनदेन की पुष्टि भी की है। किसान ने बताया कि वह शक्रवार को अपनी उपज लेकर खरीदी केंद्र पहुंचा था, वहां मौजूद सर्वेयर ने पैसे नही देने के कारण उपज को नही तौला। शनिवार को पैसे के लेनदेन की बात हुई फिर उपज को तौली लेकिन शनिवार को सर्वेयर ने 2700 रुपए लेने के उपरांत भी मूंग की खरीदी ऑनलाइन नहीं दिखाई । कच्ची हस्तलिखित पर्ची किसान को देकर शेष 300 रु और भुगतान कर ऑनलाइन पर्ची लेने का कहा, जिस पर किसान ने सोमवार की शाम ऑनलाइन पर्ची के लिए बकाया 300 रु दिए तब उसकी उपज को ऑनलाईन विक्रय होना दर्शाया गया! जब हमने इस मामले में किसान कल्याण तथा कृषि विकास आधिकारी केएस खपेडिया जो कि (डीडीए विदिशा)हैं। उनसे बातचीत की तो उन्होने ने पल्ला झाड़ते हुए सारी बात मार्कफेड जिला आधिकारी केएस ठाकुर पर, डालते हुए उनसे संपर्क करने को कहा और जब केएस ठाकुर से बात करना चाहिए तो उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। जब विदिशा जिला मुख्यालय का यह हाल है तो जिले के अन्य खरीदी केदो की वास्तविकता को बेहतर समझा जा सकता है ।

अब दूसरे जिले नरसिंहपुर की भी तस्वीर देखिए ।

नरसिंहपुर जिले में प्रशासन द्वारा करीब 41 मूंग उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं, लेकिन अब मूंग उपाजज्न खरीदी केन्द्रो पर वारदाने उपलब्ध नहीं कराये जा रहे। वारदाने नहीं होने के कारण मूंग विक्रय करने में किसानों को 5 से 6 दिन का इंतजार करना पड़ रहा है । वारदाने की कमी का ऐसा ही मामला लिंगा में बने मूंग उपार्जन केंद्र नायक देवी प्रभा वेयरहाउस में देखने को मिला जहां पर किसानों ने बताया कि 6 दिनों से हम कतार में लगे हुए हैं लेकिन वारदानों की कमी के कारण हमारी मूंग खरीदी नहीं हो पा रही है। इसके पहले फटे वारदाने को किसानों ने सिलकर मूंग विक्रय की अब तो फटे वारदाने भी नहीं बचे हैं। अब एक अधिकारी कहते हैं कि मार्कफेड ने दूसरे विभाग से वारदाने उधार मांगे हैं। प्रशासन को खरीदी केंद्र की तैयारियों में आखिर कहां चूक हुई कि वारदानों की कमी आ गई। जब इस बारे में डीएमओ मूलचंद कुसरे को अवगत कराया तो उन्होंने कहा कि पाली वेयरहाउस से वारदाना मंगवाए, लेकिन पाली वेयरहाउस में भी वारदाने नहीं मिल सके। किसान मायूस, बेबस होकर वेयरहाउस में तीन-चार दिनों से वारदानों का इंतजार कर रहे हैं और वेयरहाउस के बाहर लंबी-लंबी ट्रैक्टर ट्रक की लाइन लगी हुई है।

खरीदी केंद्र पर आए कृषि विभाग के अधिकारियों से भी किसानों ने शिकायत की लेकिन वह भी बेअसर

जिले के गाडरवारा तहसील में बने मूंग खरीदी केन्द्रो भी वारदानें नहीं है। उधर किसानों को अनाज देने के महीने भर गुजर जाने के बावजूद भुगतान नहीं मिला है मसलन समनापुर के बाबूलाल पटेल कहते हैं कि उन्होंने लगभग 3:30 लाख रुपए की मूंग दी लेकिन 24 जुलाई हो जाने के बावजूद उन्हें राशि का भुगतान नहीं हो सका । किसान बाबूलाल पटेल का आरोप है कि सवेज़्यर तंग करते हैं कहीं एक या दो फीसदी मिट्टी कचरा होने के बावजूद उसे लिया नहीं जाता जबकि जुगाड़ करने वालों की चार से पांच फीसदी कचरा होने पर भी आसानी से ले लिया जाता है । सर्वेयरों की मनमानी है। इन्हीं व्यवस्थाओं के कारण गांव के करीब 40प्रतिशत किसानों ने पंजीयन नहीं कराया। इसके पहले मूंग खरीदी में उपार्जन सीमा को लेकर भी किसान काफी तंग रहे इसलिए मजबूर होकर उन्होंने 7000- 7100 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से व्यापारियों को अपनी उपज बेच दी। इसके बाद जब किसने की मांग उठी तो उपार्जन सीमा और बढ़ाई गई तब तक आधे से ज्यादा किसान 8454 की बजाय करीब 7000 रु प्रति क्विंटल की दर से अपनी मूंग बेचने मजबूर हो गए । किसानों का तो अब आरोप है कि समर्थन मूल्य पर कोई भी खरीदी हो । हमेशा प्रशासन, सर्वेयरों, समिति प्रबंधकों की मनमानी चलती है इसलिए अब समर्थन मूल्य पर खरीदी बंद कर देना चाहिए ।

वैज्ञानिकों ने बताया दलहनी फसल उड़द को बीमारियों से कैसे बचाएं

टीकमगढ़। जागत गांव हमार

कृषि विज्ञान केंद्र, टीकमगढ़ के प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ. बीएस किरार साथ ही केंद्र के वैज्ञानिकों डॉ. आरके प्रजापति, डॉ. यूएस धाकड़, डॉ. एसके जाटव एवं डॉ. आई.डी. सिंह द्वारा विगत दिवस कोडिया, लहरगुवाँ एवं बीघा में दलहनी फसलों पर कृषक संगोष्ठी एवं उड़द फसल का भ्रमण किया। कृषक संगोष्ठी के दौरान वैज्ञानिकों ने किसानों को उड़द फसल में लगने वाले प्रमुख कीड़े व बीमारियों के प्रबंधन के बारे में विस्तार से बताया।

उड़द फसल में फली बीटल कीट का प्रकोप अधिक होता है। इस कीट की इल्लियाँ बीज पर तथा छोटे पौधों की पत्तियों में छेद करती हैं, जिससे पत्तियों पर छेद ही छेद दिखाई पड़ते हैं। इसी प्रकार पत्ती भेदक इल्लियाँ भी पत्तियों को खाकर पौधों को हानि पहुंचाती हैं। इसके अलावा चूसक कीटों में सफेद मक्खी, काली माहू एवं जैसिड, इस प्रकार के कीटों के साथ नियंत्रण हेतु पूर्व मिश्रित दवाएं जैसे क्लोरएन्ट्रानिलिप्रोल 9.30प्रतिशत + लॅम्बडा-सायहॅलोथ्रीन 9.50प्रतिशत जेड.सी. या थियामेथोक्सम 12.60प्रतिशत + लॅम्बडा-सायहॅलोथ्रीन 9.50प्रतिशत जेड.सी. 60 मिली या बीटासायफ्लुथ्रिन + इमिडाक्लोप्रिड 150 मिली की दर से 200 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। उड़द फसल की प्रमुख बीमारियों के अंतर्गत पीला मोजक रोग फसल को ज्यादा प्रभावित करता है।

इस रोग के विषाणु को ग्रसित पौधों से दूसरे स्वस्थ पौधों पर फैलाने का कार्य सफेद मक्खी करती है। पूर्व में दर्शायी पूर्व मिश्रित दवाओं को प्रयोग भी कर सकते हैं या केवल चूसक कीट की समस्या है तब इमिडाक्लोप्रिड (80-100 मिली) या एसिटामिप्रिड 25प्रतिशत + बायफेन्थ्रिन 25प्रतिशत WG 100 ग्राम प्रति एकड़ की दर से गोल बनाकर छिड़काव करें। लगातार बारिश होने पर सकोज़स्पोरा पणज़ दाग रोग और एन्थ्रेक्नोज रोग इन रोगों से पत्तियों पर गहरे भूरे धब्बे बनते हैं, यह धब्बे फैलते हुए शाखाओं और फलियों पर भी पड़ जाते हैं, इनसे बचाव के लिए टेबुकोनाजोल 25.9प्रतिशत ईसी 250 मिली. या टेबुकोनाजोल 10प्रतिशत + सल्फर 65प्रतिशत ड्रुल 600 ग्राम या कार्बेन्डाजिम 12प्रतिशत + मैंकोजेब 63प्रतिशत मात्रा 600 ग्राम प्रति एकड़ की दर से 200 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। दवा के प्रभावी असर हेतु छिड़काव के 3-4 घंटे तक बरसात नहीं होना चाहिए।

मंत्रियों के क्षेत्र में किसान परेशान, धरना-प्रदर्शन के लिए मजबूर

परेशान किसानों की नहीं हो रही सुनवाई, सड़क पर लगाया जाम

सीहोर/ नरसिंहपुर। जागत गांव हमार

मूंग उत्पादक किसान अपनी उपज समर्थन मूल्य पर बेचने के लिए बहुत परेशान हो रहे हैं। गुरुवार को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के विधानसभा क्षेत्र और मध्य प्रदेश में पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री के गृह नगर गोटेगांव में तंग किसानों पर सड़क पर जाम लगा दिया। काफी देर तक सड़क पर टे रहे । किसानों को समझाने की भरपूर कोशिश की गई।

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विधान सभा क्षेत्र भेरूंदा में मूंग खरीदी नहीं होने से नाराज किसानों ने सड़क पर चक्काजाम कर दिया। बड़ी संख्या में मौजूद किसानों ने जमकर नारेबाजी की। भोपाल -भेरूंदा मार्ग पर बीच सड़क पर बैठकर जाम लगा दिया। इस दौरान वाहनों की लंबी कतार लग गई। वाहन चालक परेशान होते नजर आए। किसानों के विरोध प्रदर्शन और चकाजाम करने से आम राहगीरों के लिए निकलना मुश्किल हो गया और इसके बाद पुलिस को मौके पर आना पड़ा।

समस्याओं का समाधान करने के आश्वासन पर हटाया जाम

पुलिस-प्रशासन के अधिकारियों ने किसानों को समझाने की कोशिश की, लेकिन किसान बेहद नाराज खफा थे। वे मूंग खरीदी में हो रही गड़बड़ियों को दूर करने की मांग कर रहे थे और इन गड़बड़ियों को दूर किए बगैर जाम खत्म करने को राजी नहीं हुए। काफी देर तक अधिकारियों ने किसानों को समझाईश दी, दिक्कतें दूर करने समस्या को हल करने का आश्वासन दिया तब किसान राजी हुए और आंदोलन समाप्त किया। उधर मध्यप्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल के गृह नगर गोटेगांव में भी यही हाल रहा। यहां गोटेगांव जबलपुर मार्ग स्थित एक वेयर हाउस के सामने बड़ी संख्या में जुटे किसान धरने पर बैठ गए। काफी देर तक पुलिस मान मनौव्वल करती रही । इसके बाद अधिकारियों के आश्वासन पर किसान धरने से उठे। किसानों का कहना था कि मूंग लेने में अधिकारी किसानों को तंग कर मनमानी और पक्षपात कर रहे हैं।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने स्ट्रीट फूड पंजीकरण शुल्क माफ करने के दिये निर्देश

स्ट्रीट फूड वेंडर्स का अब एफएसएसएआई पंजीयन निःशुल्क

भोपाल/नई दिल्ली। जागत गांव हमार

दिल्ली के विज्ञान भवन में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा ने भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) द्वारा 1,000 स्ट्रीट फूड विक्रेताओं के लिए आयोजित प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम में एफएसएसएआई पंजीकरण शुल्क माफ करने की घोषणा की है, अभी तक पंजीयन शुल्क 100 रुपये वार्षिक लिया जाता था। स्ट्रीट फूड वेंडर को खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे पी नड्डा ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल भी उपस्थित थीं। भारत में स्ट्रीट फूड के महत्व पर प्रकाश डालते हुए नड्डा ने एफएसएसएआई को स्ट्रीट फूड विक्रेताओं के लिए 100 रुपए का पंजीकरण शुल्क माफ करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा, विक्रेताओं को प्रोत्साहित करने और अधिक से अधिक पंजीकरण को बढ़ावा देने के लिए, एफएसएसएआई स्ट्रीट फूड विक्रेताओं के लिए 100 रुपये का पंजीकरण शुल्क माफ कर देगा।

स्ट्रीट फूड विक्रेताओं प्रदान की जाएगी अभिनव स्ट्रीट सेफ त्वरित जांच किट

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, देश भर में स्ट्रीट फूड विक्रेताओं द्वारा सुरक्षित भोजन का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं प्रमाणन (एफओएसटीएसी) प्रशिक्षण में भाग ले रहे सभी विक्रेताओं को अभिनव 'स्ट्रीट सेफ त्वरित जांच किट प्रदान की जानी चाहिए। उन्होंने आगे कहा, इसके अलावा, हमें स्ट्रीट फूड विक्रेताओं को उपभोक्ताओं तक उनकी पहुंच बढ़ाने के लिए खाद्य वितरण प्लेटफार्मों पर नामांकित करके उन्हें सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मैं इन प्लेटफार्मों से वित्तीय बोझ डाले बिना उपयोगकर्ता-अनुकूल प्रौद्योगिकी समाधान प्रदान करके स्ट्रीट फूड विक्रेताओं का समर्थन करने का आग्रह करता हूं। श्री नड्डा ने स्ट्रीट फूड विक्रेताओं खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण को अपने दैनिक जीवन में व्यावहारिक रूप से लागू करने के लिए प्रोत्साहित किया, ताकि हमारी पारंपरिक स्ट्रीट फूड संस्कृति सभी के उपभोग के लिए सुरक्षित रहे। उन्होंने कहा, यह मेरा दृढ़ विश्वास है कि यदि विक्रेता सुरक्षित तौर-तरीकों और स्वच्छता को लागू करेंगे, तो उनके व्यवसायों में भी वृद्धि होगी। उन्होंने आगे कहा कि प्रशिक्षित विक्रेताओं को एफएसएसएआई से मिलने वाले प्रमाण पत्र भी उनके व्यवसाय को बढ़ावा देंगे, क्योंकि यह उपभोक्ताओं के बीच विश्वसनीयता का स्रोत बनेगा।

फूड वेंडरों को ट्रेनिंग दी गई ट्रेनिंग मैन्युअल जारी किया

स्ट्रीट फूड विक्रेताओं के इस कार्यक्रम में 'हाकर्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी' की संगठन राष्ट्रीय महासचिव सुषमा शर्मा और कार्यकारी अध्यक्ष एच एस रावत के साथ दो सौ से ज्यादा स्ट्रीट फूड वेंडर शामिल हुए। एफएसएसएआई के नेशनल रिसोर्स पर्सन धर्मेंद्र कुमार द्वारा भी उपस्थित फूड वेंडरों को ट्रेनिंग दी गई, वही धर्मेंद्र कुमार ट्रैनिंग मैन्युअल कमेटी के पैनल डिस्कशन में भी शामिल रहें। केंद्रीय मंत्री जे पी नड्डा, केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल, एफएसएसएआई के सीईओ जी कमला वर्धन राव, एफएसएसएआई के कार्यकारी निदेशक यू एस ध्यानी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के उच्चाधिकारियों द्वारा एफएसएसएआई का ट्रेनिंग मैन्युअल जारी किया, आपको बता दे कि धर्मेंद्र कुमार मैनुअल ड्राफ्ट कमिटी के पैनल मेंबर भी हैं।

कृषि मंत्री का संसद में दावा

किसानों की पूरी तुअर, उड़द और मसूर खरीदेगी सरकार

भोपाल/नई दिल्ली। जागत गांव हमार

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को राज्यसभा में बजट पर चर्चा में हिस्सा लिया। भारी शोर और हंगामे के बीच कृषि मंत्री ने संसद सदस्यों का जवाब दिया। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में अधिकतम एमएसपी पर फसलों की खरीद हुई है। इस साल भी तुअर, मसूर और उड़द जितनी किसान उपजाएगा, सरकार उसे खरीदेगी। सरकार ने उसके लिए समृद्धि पोर्टल बनाया है। किसान इस समृद्धि पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराएं, सरकार उसकी पूरी उपज खरीदेगी।

शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आंकड़े गवाह हैं कि जब इनकी (कांग्रेस) सरकार थी तो एमएसपी पर उपज की कितनी खरीद होती थी। और जब हमारी सरकार है तो कितनी खरीद हो रही है। ये सरकार किसानों के हित की सरकार है और किसानों के हित में लगातार फैसला हो रहा है। संसद में कृषि मंत्री ने कहा, दलहन की खरीद 2004-05 से 2014-15 तक केवल 6 लाख मीट्रिक टन थी जो अब बढ़कर 1 करोड़ 67 लाख टन हो गई है। तिलहन की खरीद कांग्रेस सरकार में केवल 50 लाख टन थी जो अब बढ़कर 87 लाख मीट्रिक टन हो गई है।

सरकार ने बढ़ाई एमएसपी

केंद्र सरकार ने दाल खरीद दर यानी न्यूनतम समथज्न मूल्य रेट को बढ़ाया है, जो किसानों को दाल बुवाई के लिए प्रेरित कर रहा है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार अरहर, मूंग, उड़द दाल का एमएसपी 2023-24 सीजन के लिए केंद्र सरकार ने बढ़ाया है। तुअर यानी अरहर दाल का एमएसपी रेट 2023-24 सीजन के लिए 400 रुपये बढ़ाकर 7000 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। मूंग दाल की एमएसपी 2023-24 सीजन के लिए सरकार ने 800 रुपये बढ़ाकर 8558 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। उड़द दाल की एमएसपी 2023-24 सीजन के लिए सरकार ने 350 रुपये बढ़ाकर 6950 रुपये प्रति क्विंटल किया है।

एमएसपी पर क्या बोले कृषि मंत्री

शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पहले की सरकार में कपास की खरीद केवल 36 हजार गांठ की थी जिसे हमारी सरकार ने बढ़ाकर 1 लाख 31 हजार गांठ कर दी है। संस्थागत ऋण उस सरकार में 7 लाख 31 लाख करोड़ रुपये ही मिलता था जिसे मौजूदा सरकार ने बढ़ाकर 25 लाख करोड़ रुपये कर दिया है। पूर्व सरकार में धान के न्यूनमत समर्थन मूल्य पर खरीद का लाभ केवल 78 लाख किसानों को मिलता था जबकि मौजूदा सरकार में 1 करोड़ 3 लाख 82 हजार किसान हो गए हैं। गेहूं की खरीद के लिए न्यूनतम समथज्न मूल्य से लाभान्वित होने वाले किसान केवल 20 लाख थे जो बढ़कर 22 लाख 69 हजार हो गए।

दलहन पर क्या बोले कृषि मंत्री

अभी हाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस में चौहान ने बताया किसानों के पंजीकरण के लिए भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (नेफेड) और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड (एनसीसीएफ) के माध्यम से ई-समृद्धि पोर्टल शुरू किया गया है। सरकार पोर्टल पर पंजीकृत किसानों से एमएसपी पर इन दालों की खरीद करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने राज्य सरकारों से आग्रह किया कि वे अधिक से अधिक किसानों को इस पोर्टल पर पंजीकरण करने के लिए प्रोत्साहित करें ताकि वे सुनिश्चित खरीद की सुविधा का लाभ उठा सकें। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश इन तीनों फसलों के उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं है और 2027 तक आत्मनिर्भरता हासिल करने का लक्ष्य है। चौहान ने 2015-16 से दालों के उत्पादन में 50 प्रतिशत की वृद्धि करने के लिए राज्यों के प्रयासों की सराहना की, लेकिन प्रति हे. उपज बढ़ाने और किसानों को दालों की खेती के लिए प्रेरित करने के लिए और अधिक प्रयास करने का आह्वान किया। उन्होंने सराहना की कि देश ने मूंग और चना में आत्मनिर्भरता हासिल की है और उल्लेख किया कि देश ने पिछले 10 वर्षों के दौरान आयात पर निर्भरता 30 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दी है।

पशुपालकों के लिए आई खुशखबरी, बढ़ेगा डेयरी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट, सरकार उठा रही ये कदम

भोपाल/नई दिल्ली। डेयरी पशुपालकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। जल्द ही सरकार एक ऐसा काम करने जा रही है जिससे दूध उत्पादन और उसकी खपत दोनों ही बढ़ेंगे। और ये सब मुमकिन होगा डेयरी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट से। अभी तक कुछ अड़चन के चलते डेयरी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट रफ्तार नहीं पकड़ पा रहा है। इसके पीछे एक सबसे बड़ी वजह है पशुओं की बीमारी खुरपका-मुंहपका लेकिन अब सरकार एफएमडी को लेकर एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। इसी तरह का कदम सरकार ने प्रोल्ट्री सेक्टर में भी उठाया है। इसके बाद अंडों का एक्सपोर्ट बढ़ गया है। केन्द्रीय डेयरी और पशुपालन मंत्रालय में आयोजित बैठक के दौरान इस प्लान पर चर्चा की गई है। मंत्रालय में सचिव अलका उपाध्याय का कहना है कि एफएमडी डिजिज फ्री कंपार्टमेंट जोन बनाकर डेयरी एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए देश के नौ राज्यों के साथ मिलकर काम किया जाएगा। इसके लिए कुछ ऐसे पाइंट भी तैयार किए गए हैं जिनका पालन कर एफएमडी को कंट्रोल किया जाएगा। एनिमल एक्सपटज् की मानें तो सरकार के इस कदम का असर मीट एक्सपोर्ट पर भी पड़ेगा। क्योंकि यूरोपियन समेत कई ऐसे देश हैं जो भारतीय बफैलो मीट को पसंद तो करते हैं, लेकिन एफएमडी के चलते उसकी खरीद नहीं करते हैं।

ऐसे बनाए जाएंगे एफएमडी डिजिज फ्री कंपार्टमेंट जोन

मंत्रालय से जुड़े जानकारों की मानें तो मंत्रालय पोल्ट्री की तरह से ही एफएमडी डिजिज फ्री कंपार्टमेंट जोन बनाने पर काम करेगा। जोन के लिए पशुपालक अपना हलफनामा देंगे कि उनके पशुओं में एफएमडी बीमारी नहीं है। इस पर मंत्रालय भी काम करेगा और फिर उसे वर्ल्ड हैल्थ ऑर्गनाइजेशन को भेजा जाएगा। डब्ल्यूएचओ इसकी जांच करने के बाद उस पर अपनी मुहर लगाएगा। इसके बाद उस एफएमडी डिजिज फ्री कंपार्टमेंट जोन में आने वाले राज्य या फिर शहर और ब्लॉक के पशुपालक अपना दूध उन डेयरी प्लांट को बेच सकेंगे जो एक्सपोर्ट के लिए डेयरी प्रोडक्ट तैयार करते हैं। ऐसा होने के बाद जहां दूध की डिमांड बढ़ेगी तो उसका उत्पादन भी बढ़ेगा। मीटिंग के दौरान एनएफएमडी के निदेशक डॉ. आरपी सिंह भी मौजूद थे। गौरतलब रहे मंत्रालय ने इसी तरह से देश के अलग-अलग राज्यों में पोल्ट्री के 26 डिजिज फ्री कंपार्टमेंट जोन बनाए हैं। इन्हें डब्ल्यूएचओ से भी मान्यता मिली हुई है। इसका मतलब ये है कि इन 26 इलाकों के पोल्ट्री प्रोडक्ट में वो बीमारियां नहीं हैं जिनके चलते अंडों का एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा था। और अच्छी बात ये है कि ऐसा होने के बाद अंडों के एक्सपोर्ट में तेजी आई है।

जागत गांव हमार के सुधि पाठकों...

» जागत गांव हमार कृषि, पंचायत और ग्रामीण विकास आधारित समाचार पत्र है, जिसके लिए आपका स्नेह और प्यार हमें शुरू से मिलता रहा है। हम आशा और विश्वास करते हैं कि आगे भी मिलता रहेगा।

» समाचार पत्र के लिए विशेषज्ञों की राय, प्रकाशन योग्य सामग्री के साथ-साथ आपके समक्ष इसे पहुंचाने तक हमारी जिम्मेदारी बड़ी चुनौतीपूण है। आपके सहयोग से ही हम इस चुनौती का सामना कर पाएंगे।

» ऐसे में हमारी आपसे अपेक्षा और आग्रह है कि जागत गांव हमार के वार्षिक सदस्य बनें और इसके लिए नीचे लिखे गए नंबर पर संपर्क करें।

संपर्क करें- अजय द्विवेदी-9229497393, 94250485889

"आपका सहयोग हमारी मजबूती का आधार बनेगा"

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक अजय कुमार द्विवेदी द्वारा जय माता प्रिंटर्स, मं.नं.1, पेमदीपुरा बापू कालोनी के पास चिकलोद रोड, जहांगीराबाद, भोपाल(मप्र) से मुद्रित एवं एमआईजी 30, शिवकल्प, अयोध्या बाईपास भोपाल, मप्र से प्रकाशित। संपादक: अजय कुमार द्विवेदी, **संपर्क** -9229497393, 9425048589, ईमेल:- jagatgaon.bpl@gmail.com (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल होगा)